



शिक्षा विवरण

त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे नर्मदापुरम् संभाग सीहोर जिले एवं जबलपुर से एक साथ प्रकाशित एकमात्र समाचार-पत्र

प्रेरणापुंज -विचित्र कुमार सिन्हा वर्ष-31 अंक-51 नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) बुधवार 02 अप्रैल 2025 पृष्ठ-8 मूल्य -1 रुपये सम्पादक- कृष्णाकान्त सक्सेना

सीएम राइज स्कूल कहलाएंगे अब सांदीपनि विद्यालय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भगवान श्रीकृष्ण ने की थी सबसे पहले "स्कूल चलें हम" अभियान की शुरुआत

भोपाल(निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गणवेश, लैपटॉप, ई-स्कूटी, साइकिल, कोचिंग के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा कर सही अर्थ में रामराज की कल्पना को साकार कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में मध्यप्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। प्रदेश के समस्त निर्मित और निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूलों का नाम अब सांदीपनि विद्यालय होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (ओल्ड कैम्पियन) में आयोजित स्कूल चलें हम राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम-2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीन विद्यालय परिसर पहुंचने ही विद्यार्थियों से संवाद किया और इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी देखी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों का अवलोकन कर सराहना की।



वालिकाओं को उपहार दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और अन्य अतिथियों ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्ट्रूट डायरेक्टरी मैनजमेंट सिस्टम से किए जाने और इस पोर्टल में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कार्यों को शामिल



तो उस समय की परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। वह प्रथम स्कूल चलें हम अभियान था। भगवान श्रीकृष्ण ने ही यह अभियान प्रारंभ किया। भगवान श्रीकृष्ण ने कंस के कुशासन का अंत कर शिक्षा का महत्व प्रतिपादित किया। उस युग के ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कि श्रीकृष्ण को शिक्षा के लिए गोकुल भेजा जाए जो सांदीपनि आश्रम था। यहीं पर श्रीकृष्ण और सुदामा की अनुरूपी मित्रता

बहादुर शास्त्री ने भी अभाव और निर्धनता में रहकर कष्ट सहते हुए शिक्षा ग्रहण की, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का भी उल्लेख किया जिन्होंने कठिन बाल्य काल और चाय की दुकान पर कार्य करते हुए आगे बढ़ते हुए परिश्रम से सम्मान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में संभाग स्तर पर सफलतापूर्वक इंस्टीट्यूट ऑन-क्लेव हुए। उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना में कदम बढ़ाए हैं। ऐसे उद्योगपतियों की संख्या 60 प्रतिशत है। राज्य शासन उद्योगों को समय-सोमा में भूमि के साथ अन्य सुविधाएं दे रहा है। लक्ष्य यही है कि विद्यार्थियों को और युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिलवाया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भोपाल में रात्रि विश्राम भी किया। भोपाल को राजधानी के अनुरूप इस समिट के आयोजन का सौभाग्य मिला। समिट के लिए स्थान की समस्या बताई गई थी लेकिन राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की, उससे सभी संतुष्ट हुए और उद्योगपतियों ने टेंट में रुकने में भी संकोच नहीं किया। संपूर्ण आयोजन अभूतपूर्व हो गया।

दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट पेश, निगरानी और निरीक्षण प्रणाली में मिली कई खामियां



नई दिल्ली(आरएनएस)। दिल्ली विधानसभा में आज वायु प्रदूषण को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों द्वारा तैयार आंकड़ों में संभावित अशुद्धियां, प्रदूषक स्रोतों पर वास्तविक समय की जानकारी का अभाव और सार्वजनिक परिवहन बसों की कमी समेत कई कमियां गिनाई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या मानकों के अनुसार नहीं थी, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक डेटा विश्वसनीय नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में बसों की कमी है। 9,000 जरूरी बसों के मुकाबले केवल 6,750 ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा बस प्रणाली में संचालन की अक्षमताएं जैसे बसों का ऑफ-रोड रहना, मार्गों की कम कवरेज और मार्गों को तर्कहीन बनाने से नुकसान की बात भी कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2011 के बाद से जनसंख्या में 17 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, लेकिन ग्रामीण-सेवा वाहनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि उचित वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए आवश्यक प्रदूषक सांद्रता डेटा उपलब्ध नहीं था और हवा में सीसे के स्तर को भी नहीं मापा गया।

वक्फ बिल पर वोटिंग के लिए BJP ने जारी की व्हिप, सभी सांसदों को हाजिर रहने का निर्देश



नई दिल्ली(आरएनएस)। केंद्र सरकार बुधवार को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। हालांकि, विधेयक पेश होने से पहले ही सियासत गर्म है। विपक्षी दलों के नेता इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए इसे मुस्लिमों के हित में बताया है। इस विधेयक को लेकर लोकसभा में बुधवार को वोटिंग होनी है। इसके लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कम्पैस ली है। भाजपा ने मंगलवार को ही व्हिप जारी कर दिया है और अपने सभी सांसदों से लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। पार्टी की ओर से जारी व्हिप में कहा गया कि बुधवार को सदन में अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य है। उन्हें पारित करने के लिए सभी लोग पार्टी का समर्थन करें और वोटिंग करें। व्हिप में सभी सांसदों से पूरे दिन सदन में ही मौजूद रहने को कहा गया है। भाजपा के पास लोकसभा में 240 सांसद हैं। सरकार जेडीयू और टीडीपी पर निर्भर है। ऐसे में देखा दिलचस्प होगा कि इस विधेयक को लेकर किस दल का क्या रुख रहेगा। अब तक चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर ने खुलकर समर्थन नहीं किया है, लेकिन विपक्ष को मुसलमानों को डराने से बचने की को नसीहत दी है। इसी तरह जेडीयू का स्टैंड भी क्लियर नहीं है।

ललन सिंह ने कहा कि हम लोकसभा में ही अपना रुख स्पष्ट करेंगे। इसके चलते सस्पेंस भी बढ़ गया है कि आखिर क्या होगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजजू ने दावा किया है कि सरकार को अपने सहयोगी दलों के अलावा विपक्ष के भी कुछ सांसदों का समर्थन हासिल है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि विधेयक पर सदन में आठ घंटे की प्रस्तावित चर्चा के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजजू जवाब देंगे। इस विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की मंजूरी लेंगे।

पकड़ा गया खालिस्तानी आतंकी पन्तू का झूठ, एक चिट्ठी से सच हुई भारत की बात

नई दिल्ली (ए)। अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ आग उगलने वाला खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्तू का झूठ पकड़ा गया। उसने अमेरिकी अदालत को बरगलाने की पूरी कोशिश की। उसने अजीत डोभाल के समन को लेकर झूठ बोला। मगर उसकी दाल नहीं गल पाई और झूठ पकड़ी गई। खालिस्तानी आतंकी पन्तू के वकील ने कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी थी जिसके बाद अदालत ने ये प्रतिक्रिया दी है। इस चिट्ठी में खुलासा हुआ है कि जब आतंकी पन्तू के सर्वर (समन लेकर जाने वाला) ने ब्लैयर हाउस (जहां भारतीय प्रतिनिधिमंडल रुका था) के बाहर नोटिस देने की कोशिश की तो राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी। इसके बाद आतंकी पन्तू के सर्वर ने उस समन को पास के एक स्टारबक्स स्टोर पर ही छोड़ दिया, जो कोर्ट के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक के साथ।

सरकार का सख्त एक्शन, घटिया दवाओं पर रोक के आदेश

नई दिल्ली(आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को फर्मा कंपनियों से कहा कि वे गुणवत्ता के मानक पर खराब घोषित की गई दवाओं को तुरंत वापस लें तथा उसका आग वितरण बंद करें। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। राज्यसभा सांसद संजय कुमार द्वारा रिजिस्ट्रार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके दवा की गुणवत्ता के मुद्दों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग को मजबूत करने की योजना पर उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए, पटेल ने कहा कि सीडीएससीओ की दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, सुगम लैब सिस्टम 2023 से लागू हैं, उन्होंने कहा, यह गुणवत्ता विनिर्देश को पूरा करने और प्रयोगशालाओं में परीक्षण की स्थिति का पता लगाने के लिए चिकित्सा उत्पादों (ड्रग्स, वैक्सिन, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों) के परीक्षण के लिए संपूर्ण कार्यप्रवाह को स्वचालित करता है। पटेल द्वारा संसद में दिया गया यह बयान इस तथ्य के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि हर महीने सीडीएससीओ विभिन्न दवा कंपनियों द्वारा निर्मित विभिन्न दवाओं को मानक गुणवत्ता के नहीं होने का पता लगता है।



चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के मुद्दों को सुलझाने के लिए कीं 5000 बैठकें

नई दिल्ली,(आरएनएस)। भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने राजनीतिक दलों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने हाल ही में देश भर में विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 5,000 बैठकें की हैं। इन बैठकों का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी लंबित मुद्दे को हल करना था। चुनाव आयोग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 25 दिनों की अवधि में कुल 4,719 बैठकें हुईं। इन बैठकों का विवरण इस प्रकार है: 40 बैठकें राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) द्वारा आयोजित की गईं, 800 बैठकें जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा आयोजित की गईं, 3,879 बैठकें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा आयोजित की गईं। चुनाव आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया में देश भर में राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शामिल थी।



उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया 10-10 लाख मुआवजे का आदेश



नई दिल्ली, (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्राधिकरण को यह मुआवजा 6 हफ्ते के भीतर देना होगा। कोर्ट ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है और प्राधिकरण ने घर गिराने की प्रक्रिया

मनमानी तरीके से की 2021 में प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के मकान तोड़ दिए गए थे इन लोगों को 6 मार्च, 2021 को नोटिस दिया गया था। आरोप था कि ये जमीन दिवंगत गैंगस्टर अतीक अहमद के नाम पर थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर और अपील का समय दिए बिना ही मकान तोड़े गए। बाद में याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने कहा, घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम भी कोई चीज होती है। उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से भी ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है, ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज कर सकें। फैसले पर अखिलेश यादव ने लिखा, इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सच तो ये है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसे से भरा जा सकता है।

